

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2007 - माघ 6, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक 32/929/2006/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 8-1-2007 से 12-1-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 7, 13 एवं 14-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री एस. आर. सेजकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री विजय कुमार सिंह का कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव।

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/6/2004/1/2.—श्री आर. पी. बगई, भा. प्र. से., मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 11-01-2007 से 12-01-2007 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 13 एवं 14 जनवरी, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री बगई आगामी आदेश तक मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री बगई को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बगई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव।

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 4-10/2003/1/एक.—राज्य शासन, माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 से 08 नवम्बर, 2006 तक (कुल 10 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की एतद्द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव।

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1398/1011/2006/1-8/स्था.—श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 22-12-2006 से 12-1-2007 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1400/1087/2006/1-8/स्था.—श्री अजय कुमार पाण्डे, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 5-12-2006 से 8-12-2006 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 9 एवं 10-12-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार पाण्डे को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार पाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1402/1068/2006/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26-12-2006 से 6-1-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24, 25-12-2006 एवं दिनांक 7-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री विलियम कुजूर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1404/1111/2006/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम (भावसे), सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 1-1-2007 से 12-1-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13 एवं 14-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्रमणियम को सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक 67/1113/2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, सचिव के स्टाफ ऑफिसर, सहकारिता विभाग को दिनांक 2-1-2007 से 19-1-2007 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय को सचिव के स्टाफ ऑफिसर, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजयवर्गीय, अवकाश पर नहीं जाते तो, सचिव के स्टाफ ऑफिसर, सहकारिता विभाग के पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक 69/08/2006/1-8/स्था.—श्री बी. एल. पवार, मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 2-1-2007 से 6-1-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवार को मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पवार, अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 417/50/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री भूपेन्द्र सठौड़, अधिवक्ता, जिला-महासमुंद को दिनांक 26-10-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए महामसुंद जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 422/50/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री अजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला-महासमुंद को दिनांक 16-7-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए महामसुंद जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 1-115/2004/सत्रह/एक.—राज्य शासन एतद्वारा लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थाई रूप से आगामी

आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक (1)	लो. से. आ. का पंजी (2)	नाम (3)	पदस्थापना स्थान (4)
1.	429,	डॉ. संतोष सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर जिला सरगुजा
2.	883	डॉ. अनिल कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरेगांव जिला कवर्धा

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- (क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा.
- (ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाये किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.
- (ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.
- (घ) छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम-1988 के नियम-19 के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर होगी.
- (च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.
- (छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अतः जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडर टेकिंग कार्य ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.
- (ज) चयनित/अभ्यर्थियों/चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-6/16/06.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदनी रोड, भिलाई एवं कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है।

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/सी. जी. आई. आर./06

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-6/16/06.—चूँकि कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदनी रोड भिलाई जिला-दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा और जनरल सेक्रेटरी, सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदनी रोड भिलाई जिला दुर्ग के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है।

और चूँकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णायार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णायार्थ सौंपता हूँ।

अनुसूची

1. क्या लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा में कार्यरत ठेका श्रमिकों को वर्ष 2004-05 के लिये 20% की दर से बोनस एवं 2700/- एक्सग्रेसिया राशि नियमित कर्मचारियों के समान दिया जाना उचित होगा ? यदि हां तो नियोजक को इस संबंध में क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-7/16/06.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियटर) को निर्दिष्ट महासचिव, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन कर्मचारी महासंघ बस स्टैण्ड पंडरी, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा :- मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है।

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 8/सी. जी. आई. आर./2004

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-7/16/06.—छत्तीसगढ़ अधोसंरचना, विकास निगम द्वारा :- मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन-कर्मचारी महासंघ, बस स्टैण्ड पंडरी रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक छत्तीसगढ़ अधोसंरचना, विकास निगम द्वारा :- मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णायार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णायार्थ सौंपता है.

अनुसूची

1. क्या सेवा नियुक्तों को समझौता दिनांक 03-02-1988 के अनुसार भुगतान प्राप्त करने की पात्रता आवेगी? यदि नहीं तो वे जिस सहायता के पात्र हैं तथा इस संबंध में सेवायोजकों को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए?

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-8/16/06.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इटक) आरसमेटा गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा एवं कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/सी. जी. आई. आर./05

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-8/16/06.—चूंकि लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इटक) आरसमेटा गोपाल नगर, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णायार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूँ.

अनुसूची

1. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट में कार्यरत समस्त श्रमिकों को सोनाडिह जोजोबेरा सीमेंट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के समान वेतन एवं सभी स्थायी सुविधाएं दिया जाना चाहिए ?
2. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट के बदली कामगारों को जो 20 वर्षों से कार्यरत हैं, प्लांट में खाली जगह वाले एरिया में स्थायी किया जाना उचित होगा. यदि हां तो इस संबंध में निथोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक 188/भू-अर्जन/2006.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदेली प.ह.नं. 6	0.266	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-5, खरसिया	सक्ती उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक/66/प्र. 1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडी लोहारा	राघोनवागांव प. ह. नं. 7	10.02	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक/67/प्र. 1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडी लोहारा	भरनाभाट प. ह. नं. 9	4.91	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व-विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 1 अ-82/2006-2007.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पकनी	1.558	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2006-2007.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	डांड अमोरनी	2.846	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 3 अ-82/2006-2007. —चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	1.598	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के शिवाजीपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 4 अ-82/2006-2007. —चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	0.968	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के सुखनईया माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 5 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	3.677	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 6 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	छतरंग	1.303	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	छतरंग जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 7 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	त्रिपुरेश्वरपुर	5.780	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	पियुरी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 1 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा (धौरपुर)	नागम	0.610	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्डा (धौरपुर)	पसेना	8.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	रूमगा	1.070	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डुरोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मटियाडांड	1.924	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	सधवानी	6.798	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	आन्दुल जलाशय (जोगीडोंगरी जलाशय) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007,

क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	सारबहरा	40.088	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	आन्दोल जलाशय (जोगीडोंगरी जलाशय) द्वय क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	आन्दू	20.217	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	आन्दोल जलाशय (जोगीडोंगरी जलाशय) द्वय क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन
उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 जनवरी 2007

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 157/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-जोगरा, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
340/3	0.040
341/2	0.024
342	0.101
364/2, 4	0.121
366/3	0.065
366/6	0.134
414/6	0.045
414/7	0.085
योग	8
	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

क्रमांक 22/प्र. 1/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बालोद
(ग) नगर/ग्राम-चिहरो, प. ह. नं. 55
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
676	0.73
680	0.25
700	2.09
516	0.07
520	0.25
521	0.37
523	0.88
681	0.30
696	0.44
690/1	0.17
691	0.26
527	0.19
705	0.52
524	1.29
529	0.08
531	0.02
699	0.69
519	0.68
706	0.70
682	0.29
683	0.27
698	0.77
703	2.93

(1)	(2)
694	0.21
508	0.74
509	0.06
510	0.15
511	0.19
512	0.17
513	0.07
514	3.75
518	0.47
522	0.26
704	0.63
707	1.14
678	0.22
679	0.47
515	0.07
517	0.02
योग	22.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमाडूला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौणडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक 32/प्र. 1/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बालोद
(ग) नगर/ग्राम-पंचेड़ा, प. ह. नं. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532	0.01

(1)	(2)
536	0.01
542	0.02
540/2	0.86
540/3	0.07
553	0.10
559	0.92
560	0.82
558/2	0.30
558/3	0.30
564	0.43
610/1	0.45
610/2	0.02
611	0.06
613	0.47
612	0.15
580	0.25
581	0.09
570	0.18
568	0.02
567	0.11
566	0.30
565	0.49
योग	6.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पंचेड़ा जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौणडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 25/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-			
(क) जिला-रायपुर		155	0.013
(ख) तहसील-आरंग		156	0.081
(ग) नगर/ग्राम-अकोलीकला, प. ह. नं. 147/45		160	0.090
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर		212	0.025
		162	0.154
		181	0.066
		182	0.512
		192	0.199
		194	0.058
		196	0.062
		202	0.019
		203	0.023
		204	0.066
		205	0.028
		214	0.024
		215	0.002
		866	0.074
		1093	0.062
खसरा नम्बर			
रकबा			
(हेक्टेयर में)			
(1)	(2)		
283	0.06		
योग	0.06		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर शाखा क्र. 19 के माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग, अभनपुर, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 1 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पकनी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

योग 18 1.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्ना जलशाय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक -2 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डांडअमोरनी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		504	0.043
		513/2	0.034
9	0.026	308	0.145
10	0.043		
11	0.043	योग	47 2.846
12	0.049		
14	0.014	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के	
15	0.057	दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
16	0.057	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर	
17	0.005	के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
18	0.069		
35	0.032		
111	0.016		
115	0.036		
167	0.075		
112	0.016		
113	0.020		
151	0.081		
114	0.025		
149	0.065		
117	0.041		
118	0.326		
146	0.081		
147	0.020		
148	0.049		
152	0.105		
153/2	0.089		
154	0.065		
155	0.065		
157	0.106		
290	0.005		
311	0.081		
291	0.049		
312	0.033		
292	0.113		
316	0.020		
303/1	0.049		
303/2	0.049		
303/3	0.041		
303/4	0.045		
304	0.009		
314	0.066		
313	0.089		
506	0.114		
315	0.041		
503	0.134		

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 3 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.598 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1450/2	0.089
1452	0.093
1453	0.028
1455	0.025
1511	0.013
1466	0.081
1477/1	0.097
1479	0.045
1481	0.129
1482	0.065

(1)	(2)
1483	0.006
1490/1	0.089
1491	0.069
1492	0.210
1498/1	0.032
1510	0.028
1575	0.073
1578/3	0.004
1580	0.121
1586	0.162
1587	0.057
1093	0.013
1497	0.049
योग	23 1.598

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के शिवानीपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 4 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
514/2	0.041
734	0.021

(1)	(2)
739	0.069
742	0.041
826	0.069
841	0.081
842	0.100
843	0.081
844	0.044
846	0.061
847	0.009
834/1	0.044
834/2	0.073
898/3	0.202
950	0.032
योग	15 0.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के सुखनईया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 5 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.677 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435/1	0.041
924	0.008

(1) (2) सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

972	0.226
1089	0.089
1094	0.008
928/1	0.647
1102/2	0.089
928/2	0.020
1102/1	0.121
1104	0.085
929	0.121
937/1	0.008
940	0.202
941	0.033
942	0.101
943	0.073
950	0.243
953	0.024
952	0.073
974	0.097
975	0.121
982	0.065
983	0.016
984/2	0.041
984/3	0.008
989	0.121
990	0.057
993/1	0.024
1002	0.049
994	0.178
998	0.089
1001	0.089
1003	0.004
1090	0.041
1091	0.089
1092/2	0.132
1093	0.105
1101	0.129

योग 38 3.677

क्रमांक - 6 अ-82/2006-2007.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-छतरंग, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
301	0.129
304	0.049
307	0.008
401	0.008
309	0.024
310	0.067
311	0.018
318/1	0.138
318/1	0.016
321	0.024
322	0.004
400	0.115
323	0.014
324	0.107
327	0.204
325	0.034
345	0.008
399	0.164
404/1	0.016
405	0.008
409	0.130
413	0.018

योग 22 1.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतरंग जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

(1)

(2)

क्रमांक - 7 अ-82/2006-2007.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-त्रिपुरेश्वरपुर, प. ह. नं. 69

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.780 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

77	0.224
86	0.376
88	0.070
87	0.048
79	0.064
89	0.030
90	0.28
91	0.10
92	0.20
117	0.08
118	0.088
119	0.001
120/2	0.047
122	0.096
126	0.088
127	0.128
129	0.096
171	0.083
172	0.029
173/3	0.06
174	0.080
173/2	0.06
175/3	0.09
175/2	0.09
175/1	0.09
170	0.040

168	0.10
165	0.040
193	0.010
546	0.024
164/1	0.06
504/1	0.09
164/2	0.24
178	0.05
180	0.05
507	0.020
541	0.080
620	0.024
181	0.050
508	0.040
183	0.090
182	0.045
621	0.026
185	0.120
189	0.005
196	0.150
443/2	0.090
441/1	0.025
453	0.064
444/2	0.025
452	0.09
454	0.090
478	0.148
479	0.010
500/1	0.096
616	0.033
456	0.038
506/1	0.06
506/2	0.02
543	0.040
545	0.064
549	0.070
573/1	0.08
573/3	0.080
573/1	0.080
173/1	0.060
613	0.06
575	0.064
574	0.096
606	0.128
612/2	0.070
615	0.053

(1) (2)

120/1 0.047

120/3 0.047

योग 74 5.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पियुरी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-लुण्डा (धौरपुर)

(ग) नगर/ग्राम-नागम

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/2	0.121
50/4	0.094
50/5	0.121
53	0.121
55/1	0.153
योग	0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-लुण्डा (धौरपुर)

(ग) नगर/ग्राम-पसेना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.243
12	0.182
13/4	0.071
187/1	0.192
175	0.162
42	0.182
112/1	0.016
212	0.149
180	0.174
250/4	0.024
283/3	0.097
213	0.445
348	0.040
379/15	0.061
379/12	0.040
306	0.045
1/15	0.081
29	0.016
250/8	0.024
341/3	0.016
244	0.141
165	0.020
168/1	0.121
173	0.016
215/2	0.141
257/1	0.070
283/4	0.097

(1)	(2)	(1)	(2)
301/3	0.081	179/464	0.020
375/3	0.040	304	0.064
380/3	0.060	379/9	0.020
374	0.016	387/1	0.049
1/17	0.060	382/1	0.113
245	0.101	11/4	0.028
15	0.113	13/3	0.070
343/3	0.243	185/2	0.141
33/2	0.087	33/1	0.087
176	0.070	36/2	0.028
172/1	0.093	111	0.101
177/4	0.133	174/2	0.283
220	0.121	303	0.162
257/2	0.071	293	0.032
289	0.016	282/2	0.141
301/4	0.081	286	0.012
340	0.008	305	0.020
379/7	0.057	379/8	0.016
369/3	0.040	379/11	0.049
1/18	0.081	387/9	0.049
13/1	0.070	योग	8.024
249	0.032		
387/8	0.049	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना	
36/1	0.181	के नहर निर्माण हेतु	
259	0.028	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,	
346	0.081	अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है	
179	0.101		
221	0.081		
258/1	0.141	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
291	0.162	मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव	
450/2	0.081		
379/1	0.081	कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं	
379/6	0.081	पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	
381	0.060	राजस्व विभाग	
3	0.320		
13/2	0.070		
27	0.172		
28	0.222	बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006	
37	0.016		
376	0.081		
347/1	0.093	क्रमांक 17/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात	
246	0.032	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि	
267	0.182	की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	
264	0.032	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 संन 1984	
		संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है	
		कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		405/2	0.150
(क) जिला-बिलासपुर		307	0.230
(ख) तहसील-पेण्डारोड		469	0.089
(ग) नगर/ग्राम-डोंगरिया		314/1	0.069
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.985 हेक्टेयर		315/1	0.053
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	462	0.162
		408/2	0.008
(1)	(2)	476/1	0.113
		442/2	0.008
		296/4	0.053
		303/6	0.053
306/2	0.089	444/6	0.178
474/3	0.040	296/2	0.032
311/1	0.069	303/7	0.032
313/2	0.008	304/1	0.073
455/2	0.008	522	0.154
303/8	0.024	296/3	0.028
464/1	0.194	303/2	0.081
475/1	0.053	302/5	0.053
314/4	0.012	312/3, 312/4	0.073
463/1	0.057	445/2	0.170
313/1	0.008	458	0.008
315/2	0.045	475/2	0.069
405/1	0.012	270/3	0.105
407	0.016	520/3	0.081
454	0.016	405/8, 405/9	0.012
308	0.016		
303/4	0.077		
305/7	0.028	योग	60 3.985
302/3, 302/4	0.178		
745/3	0.170	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बगड़ी जलाशय	
292	0.125	नहर निर्माण हेतु.	
520/8	0.045	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
302/2	0.053	(राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	
745/1	0.020		
293	0.020		
295	0.004		
445/1	0.020		
461	0.045		
304/2	0.020		
278	0.028		
294	0.085		
745/2	0.101		
465	0.012		
468	0.061		
521	0.089		

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 7/अ-82/01-02.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्डारोड

(ग) नगर/ग्राम-नगवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

289/2

0.065

400

0.008

238

0.061

41/4

0.154

237

0.040

283/1

0.036

398/3

0.109

398/6

0.069

305

0.166

306

0.040

289/1

0.073

396/2

0.113

304/1

0.024

393

0.073

249

0.142

447/1

0.061

54/1

0.049

282/1

0.008

397

0.121

302

0.028

53/1

0.324

319

0.089

441

0.065

442

0.024

41/5

0.085

251/1

0.166

298/2

0.024

438

0.004

439

0.134

398/1

0.040

398/5

0.105

317

0.186

42

0.028

280

0.057

285

0.057

443/2, 444/2, 445/3

0.243

(1)

(2)

247

0.049

296

0.101

297

0.053

398/4

0.061

284

0.129

316

0.008

299

0.024

38

0.040

396/1

0.069

444/1

0.324

395

0.057

394/1

0.069

446

0.057

440

0.089

288

0.077

योग

49

4.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपरखुज्जी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्डारोड

(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.859 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

533

0.162

(1)	(2)
536	0.113
599	0.162
567	0.240
443	0.730
446	0.840
488	0.101
485	0.053
532	0.081
445	0.680
498	0.069
506	0.251
537	0.158
595	0.300
486	0.069
528	0.081
499	0.097
596	0.710
525	0.016
594	0.350
598	0.120
501	0.073
568	0.295
487	0.065
489	0.008
490	0.660
493	0.032
495	0.081
492	0.028
500	0.117
517	0.117

योग	31	6.859
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चनाडोंगरी जलाशय डूब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 18/अ-82/01-02.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्डारोड

(ग) नगर/ग्राम-डाहीबहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

339

0.073

344

0.061

341

0.032

343

0.012

348

0.093

338

0.040

333

0.085

340

0.065

355

0.097

योग

9

0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डाहीबहरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 21/अ-82/2005-2006.—चूँकि राज्य शासन

को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-भरेवा, पं. ह. नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
380/1	0.097
382/4	0.073
381	0.162
382/1	0.117
योग	4 0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सकेरी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.399 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3, 4	0.097
5/5, 7	0.093
255/2	0.077
258/3	0.085
259/1, 4	0.045
259/2	0.045
260	0.077
296	0.069
261	0.097

(1)	(2)
285/2	0.073
274, 290/1	0.138
287/1	0.158
286/1	0.069
286/2	0.069
284/1	0.158
284/2	0.049

योग 16 1.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 22/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पीड़ा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.151 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89, 90, 92	0.158
93	0.097
372	0.008
101	0.004
100	0.101
110	0.045
111	0.069
122	0.073

(1)	(2)
123	0.004
140	0.057
135	0.089
136	0.178
269	0.012
132	0.004
134	0.004
287	0.057
270/1	0.061
286/1	0.069
270/2	0.061
योग	1.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 23/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-पुटपुरा, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77/4	0.109
80	0.053
79/1	0.121
95	0.073

(1)	(2)
96/1	0.020
96/2	0.085
69	0.097
68	0.085
67	0.093
61/1	0.049
65	0.045
योग	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 24/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-पथरगढ़ी, प. ह. नं. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
92/1	0.121
92/2	0.004
93, 94	0.97
135	0.069
136	0.008
133/1	0.069
139/1	0.024
138	0.004

(1)	(2)
122	0.061
109	0.008
141/1	0.028
141/2	0.053
124/2	0.045
123/1	0.057
121/1	0.024
110/1	0.008
115, 120/1	0.142
114/1	0.093
114/2	0.004
176/2	0.121
176/1, 176/5	0.142
योग	24
	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 25/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भठली, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209	0.008
210	0.089

(1)	(2)
212/2	0.028
215	0.004
429	0.121
428	0.012
403	0.053
430	0.004
773	0.057
426	0.069
427	0.049
425	0.057
400/1	0.020
400/2	0.020
401	0.073
407	0.077
404	0.004
776/1	0.057
406	0.069
405/2	0.008
759	0.057
760/2	0.105
779	0.012
761	0.040
774	0.109
775/2	0.008
772	0.004
771/1	0.057
771/2	0.093
798/2	0.020
योग	30
	1.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 28/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-पीड़ा, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.008
6, 8, 9,	0.162
204	0.012
योग	3 0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

प्र. क्र. 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
268/2	0.18
योग	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामबोड़ जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक 647/मण्डी/निर्वाचन/05-06.—कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 13 (1) के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति पेण्डा हेतु निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम :-

क्र.	उपाध्यक्ष का नाम	मण्डी का नाम एवं क्षेत्र का नाम
1.	श्रीमती कुसुम	कृषि उपज मण्डी समिति पेण्डा जिला बिलासपुर कृषक निर्वाचन केन्द्र क्र. 2

डी. एस. एल्मा,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.